गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 265
दि. 26.01.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

न्याय की विरासत हमारे हाथों में एक जिम्मेदारी है अधिकार नहीं: CJI सूर्यकांत का गोवा से गूंजता संदेश

(जीएनएस)। गोवा में आयोजित SCAORA के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय विधि सम्मेलन के समापन सत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्याय व्यवस्था को लेकर एक गहरी, आत्ममंथन कराने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि न्याय कोई जड़ संरचना नहीं है, बल्कि एक जीवंत संस्था है, जो निरंतरता और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाकर ही जीवित रह सकती है। उनका यह वक्तव्य केवल न्यायपालिका के भीतर बैठे लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर संदेश के रूप में देखा जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून न तो परिवर्तन से डर सकता है और न ही बिना विवेक के हर नई चीज को अपनाने की जल्दबाजी कर सकता है। दोनों ही स्थितियां कानून की आत्मा को कमजोर कर देती हैं।

उन्होंने कहा कि आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, जहां तकनीक, वैश्वीकरण और सोशल मीडिया ने समाज के सोचने, बोलने और प्रतिक्रिया देने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। ऐसे माहौल में न्याय की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वह अपने मूल सिद्धांतों के प्रति ईमानदार कैसे बना रहे। CJI सूर्यकांत ने अपने संबोधन में न्याय व्यवस्था के ऐतिहासिक पक्ष को रेखांकित करते हुए कहा कि कोई भी कानूनी प्रणाली अचानक नहीं बन जाती। यह सदियों के संघर्ष, विचार-विमर्श, सामाजिक टकराव, समझौतों और नैतिक साहस की लंबी यात्रा का परिणाम होती है। आज जिन अदालतों, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों पर समाज भरोसा करता है, वे किसी एक पीढ़ी की देन नहीं हैं। यह एक ऐसी विरासत है, जिसे हमें संभालकर आगे बढ़ाना है।

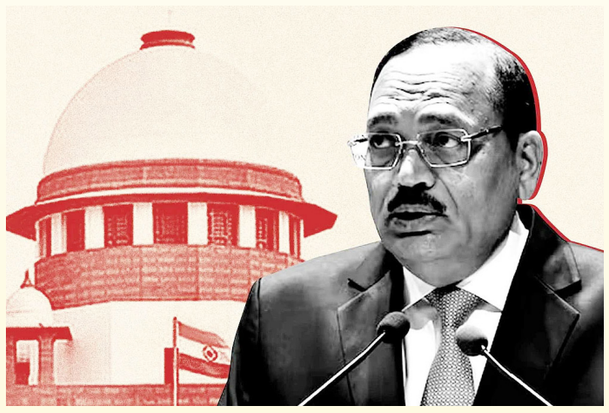

उन्होंने बेहद सटीक और विनम्र शब्दों में कहा कि आज हम जिन संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं, उन्हें हमने स्वयं नहीं बनाया है। यह बात न्यायपालिका के भीतर बैठे हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विरासत हमें विशेषाधिकार जरूर देती है, लेकिन उससे कहीं अधिक संयम और जिम्मेदारी भी सौंपती है। उनके शब्दों में, "हम न्याय संस्था के स्वामी नहीं हैं, हम केवल इसके अस्थायी संरक्षक हैं।" यह कथन अपने आप में न्यायिक सत्ता के अहंकार पर एक गहरी चोट और जिम्मेदारी की याद दिलाने वाला है।

मुख्य न्यायाधीश ने आगाह किया कि जो कानून बदलाव से दूरी बना लेता है, वह समय के साथ अप्रासंगिक हो जाता है और जो कानून बिना सोचे-समझे हर नवाचार को अपना लेता है, वह अपने नैतिक केंद्र को खो देता है। उन्होंने कहा कि न्याय की ताकत इसी में है कि वह परिवर्तन को परखे, समझे और फिर अपने मूल्यों के अनुरूप उसे स्वीकार करे। कानून का उद्देश्य केवल तेज होना नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण होना है।

अपने भाषण में CJI सूर्यकांत ने यह भी स्पष्ट किया कि आज न्यायपालिका पर जो नए दबाव दिखाई दे रहे हैं, उन्हें खतरे के रूप में नहीं देखना चाहिए। तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल अदालतें, सोशल मीडिया की त्वरित प्रतिक्रियाएं और वैश्विक संवाद, ये सभी न्याय प्रणाली की सहनशक्ति और लचीलेपन की परीक्षा हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों से आज यह अपेक्षा की जा रही है कि वे तेज भी हों और सतर्क भी, सुलभ भी हों और संयमित भी। यह संतुलन आसान नहीं है, लेकिन यही एक जीवंत संस्था की पहचान है।

मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि इन दबावों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, स्वतंत्रता का अर्थ जड़ता नहीं है और परिवर्तन का अर्थ सिद्धांतों से समझौता नहीं है। एक मजबूत न्याय व्यवस्था वही होती है जो बाहरी दबावों को अपने भीतर समाहित कर ले, बिना अपने स्वरूप और आत्मा को खोए।

उन्होंने कहा कि आज के समय में न्यायपालिका को केवल फैसले सुनाने वाली संस्था के रूप में नहीं, बल्कि समाज की नैतिक दिशा तय करने वाली संस्था के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में हर निर्णय, हर प्रक्रिया और हर सुधार का असर केवल अदालत की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज की चेतना पर पड़ता है। इसलिए जल्दबाजी में किया गया कोई भी बदलाव दूरगामी नुकसान पहुंचा सकता है।

CJI सूर्यकांत का यह संबोधन एक तरह से न्यायपालिका के भीतर आत्मसंयम और आत्मचिंतन का आह्वान था। उन्होंने यह याद दिलाया कि लोकतंत्र में संस्थाएं व्यक्ति से बड़ी होती हैं और उनकी विश्वसनीयता अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता से बनी रहती है। जब न्याय खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगता है, तभी उसके पतन की शुरुआत होती है।

गोवा से दिया गया उनका यह संदेश आने वाले समय में न्यायिक विमर्श का अहम हिस्सा बन सकता है। यह भाषण बताता है कि भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था केवल कानून की व्याख्या तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह अपने नैतिक दायित्वों और ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को भी पूरी गंभीरता से समझती है। न्याय को जीवित रखने के लिए परिवर्तन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है यह याद रखना कि हम सब इसके सेवक हैं, मालिक नहीं।

भारी बर्फबारी से जम्मू-कश्मीर में यातायात अस्त-व्यस्त, रेलवे ने चलाई विशेष ट्रेनें

(जीएनएस)। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने सामान्य जीवन और परिवहन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सड़क और हवाई मार्गों में रुकावट के बीच रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष कदम उठाया है। उत्तरी रेलवे के जम्मू डिवीजन ने श्री माता वैष्णो देवी (एसएमवीडी) कटरा और श्रीनगर के बीच 27 और 28 जनवरी को विशेष आरक्षित ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, ताकि यात्रियों को बर्फबारी के कारण परेशानी न उठानी पड़े। जम्मू के डिवीजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस समय वंदे भारत ट्रेनें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए विशेष ट्रेनें चलाना जरूरी था। इससे यात्रियों को कश्मीर आने-जाने में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी और धार्मिक तथा पर्यटन गतिविधियों पर असर कम होगा।

हाल ही में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, बनिहाल सेक्टर में भारी बर्फबारी के कारण बंद रहा। यह मार्ग दो दिनों तक यातायात के लिए बंद रहा और रविवार को आंशिक रूप से खोल गया। वहीं, कश्मीर घाटी में बर्फबारी और मौसम की खराब स्थिति के चलते हवाई सेवाएं भी बाधित रहीं। मौसम विभाग ने 26 जनवरी से 27 जनवरी

की शाम तक कश्मीर के अधिकांश इलाकों और जम्मू के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।

रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल भी जारी किया गया है। 27 जनवरी को यह स्पेशल आरक्षित ट्रेन सुबह 8:10 बजे एसएमवीडी कटरा से रवाना होकर 11 बजे श्रीनगर पहुंचेगी, और रास्ते में बनिहाल स्टेशन पर रुकाव करेगी। वापसी में यह ट्रेन दोपहर 2 बजे श्रीनगर से चलकर शाम 5 बजे कटरा पहुंचेगी। 28 जनवरी को ट्रेन सुबह 10:30 बजे कटरा से चलकर दोपहर 1:30 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। इसी दिन वापसी में ट्रेन संख्या 04630 दोपहर 3 बजे श्रीनगर से रवाना होकर शाम 6 बजे कटरा पहुंचेगी।

जम्मू के डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी और हाल ही में हुई बर्फबारी के मद्देनजर यह विशेष ट्रेन सेवा शुरू की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कदम से कश्मीर आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी और उनकी यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक होगी।

सर्दी के मौसम में इस तरह की विशेष ट्रेन सेवाएं न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, बल्कि धार्मिक, पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को भी सुचारू बनाए रखने में मदद करती हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम की जानकारी और रेलवे की सूचनाओं पर ध्यान दें और यात्रा से पहले अपडेट लें।

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी की वजह से यातायात के हालात अक्सर चुनौतीपूर्ण बने रहते हैं, लेकिन रेलवे की यह पहल यात्रियों के लिए राहत देने वाला कदम साबित होगी। इस बीच, राज्य सरकार और मौसम विभाग लगातार सड़क और हवाई मार्गों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक होने पर अतिरिक्त कदम उठाने के लिए तैयार हैं। इस वर्ष जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी की शुरुआत जनवरी की पहली सप्ताह से हुई थी और लगातार निचले इलाकों और घाटी में बर्फ जमने से कई पर्यटन स्थलों और मंदिरों तक पहुंच मुश्किल हो गई थी। स्पेशल ट्रेन सेवा के माध्यम से न केवल धार्मिक तीर्थयात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यटक और आम नागरिक भी सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकेंगे।

उचित सिंघल ने कहा कि आगामी दिनों में यदि मौसम और सड़क की स्थिति सामान्य रहती है, तो अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन सेवाओं पर भी विचार किया जाएगा। रेलवे प्रशासन का उद्देश्य है कि किसी भी तरह की असुविधा को कम किया जाए और लोगों को सुरक्षित और समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी के बावजूद रेलवे द्वारा चलाई गई विशेष ट्रेनें यात्रियों के लिए एक राहत की खबर साबित हो रही हैं और इससे राज्य में यात्रा और पर्यटन गतिविधियों को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

झारखंड की सियासत में AIMIM की नई चाल, पाकुड़ के पूर्व विधायक अकील अख्तर ने थामा ओवैसी का हाथ

(जीएनएस)। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने राज्य में अपने राजनीतिक पांव मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अकील अख्तर ने औपचारिक रूप से AIMIM की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हैदराबाद स्थित पार्टी मुख्यालय दारुस्सलाम में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में अकील अख्तर ने पार्टी का दामन थामा। इस घटनाक्रम को झारखंड की बदलती राजनीतिक तस्वीर के एक महत्वपूर्ण संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी में शामिल होने के बाद अकील अख्तर ने AIMIM के विचार और एजेंडे की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि AIMIM आज देश में उन तबकों की आवाज बन रही है, जिन्हें लंबे समय तक हाशिये पर रखा गया। अल्पसंख्यक, वंचित और कमजोर वर्गों के अधिकारों को मजबूती से उठाने वाली इस पार्टी के साथ जुड़कर वह खुद को अधिक प्रभावी भूमिका में देख रहे हैं। अकील अख्तर ने यह भी कहा कि झारखंड जैसे राज्य में सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए AIMIM एक मजबूत मंच साबित हो सकती है।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अकील अख्तर का स्वागत करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक अनुभव और जमीनी पकड़ झारखंड में पार्टी के विस्तार को नई दिशा देगा। ओवैसी ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में AIMIM राज्य में सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली राजनीतिक ताकत के रूप में उभरेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं, जहां AIMIM की विचारधारा को स्वीकार्यता मिल सकती है। इस मौके पर AIMIM के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर, प्रदेश महासचिव (संगठन) महताब आलम, प्रदेश महासचिव इंतेखाब अंसारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष कैसर इमाम और कोल्हान डिवीजन इंचार्ज सालिक जावेद की मौजूदगी ने साफ संकेत दिया कि पार्टी झारखंड को लेकर गंभीर रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। पार्टी नेतृत्व ने इसे केवल एक नेता के शामिल होने का मामला नहीं, बल्कि संगठनात्मक विस्तार की कड़ी के रूप में पेश किया। अकील अख्तर का राजनीतिक सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से की थी और पाकुड़ विधानसभा सीट से विधायक भी बने। हालांकि बाद में पार्टी से उनके रिश्ते बिगड़ गए और उन्हें छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने ऑल झारखंड स्टूडेंट पार्टी के जरिए राजनीति में अपनी सक्रियता बनाए रखी। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2024 के चुनाव में अकील अख्तर को झारखंड के सबसे अमीर उम्मीदवारों में गिना गया था, जिससे वे पहले ही चर्चा में आ चुके थे। अब AIMIM में उनकी एंट्री ने राजनीतिक चर्चाओं को फिर से तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि अकील अख्तर की आर्थिक हैसियत, राजनीतिक अनुभव और क्षेत्रीय पकड़ AIMIM के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर संताल परगना और आसपास के इलाकों में।

झारखंड में AIMIM पिछले कुछ समय से लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। पार्टी का फोकस खासतौर पर उन क्षेत्रों पर है, जहां अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों की आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। अकील अख्तर जैसे नेता का पार्टी में आना इस रणनीति को और धार देने वाला कदम माना जा रहा है। इससे न केवल संगठन को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिलेगी, बल्कि चुनावी गणित भी प्रभावित हो सकता है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि AIMIM अब झारखंड में सिर्फ सीमित प्रभाव वाली पार्टी बने रहने के बजाय, खुद को एक गंभीर राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहती है।

कांग्रेस में बयानबाज़ी का तूफान, 'जयचंद' टिप्पणी ने बढ़ाई अंदरूनी सियासी खींचतान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बार फिर सियासी बयानबाज़ी ने माहौल गरमा दिया है। वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शकील अहमद के एक बयान ने न सिर्फ पार्टी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि कांग्रेस के अंदर चल रही असहजता और असंतोष को भी सार्वजनिक कर दिया। शकील अहमद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें भारतीय राजनीति का "सबसे डरपोक और असुरक्षित नेता" बताया। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला तेज हो गया और मामला सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया। शकील अहमद ने अपने बयान में यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के दौरान वे शशि थरूर को वोट देना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों और मजबूरी के चलते उन्हें मल्लिकार्जुन खरगे का समर्थन करना पड़ा। उनके इस बयान को पार्टी नेतृत्व और संगठनात्मक प्रक्रिया पर सीधा सवाल माना गया। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे न सिर्फ अनुशासनहीनता बल्कि पार्टी के भीतर एकता को कमजोर करने वाला कदम करार दिया।

शकील अहमद के बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर की ओर से आई। टैगोर ने सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी का खुलकर बचाव किया और शकील अहमद व उनके जैसे नेताओं को "विश्वासघाती" तक कह डाला। उन्होंने लिखा कि जब साहस सबसे कठिन रास्ते पर चलता है, तब ऐसे लोगों का असली चेहरा सामने आता है, जो मुश्किल समय में पार्टी और नेतृत्व का साथ छोड़ देते हैं। टैगोर ने यह भी कहा कि कांग्रेस इस समय सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है और ऐसे वक्त में पार्टी को एकजुट रहने की जरूरत है, न कि आंतरिक हमलों की।

मणिकम टैगोर ने शकील अहमद के बयान को विचारधारा या वैचारिक चिंता से नहीं, बल्कि निजी महत्वाकांक्षा से प्रेरित बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयान टीवी डिबेट्स में जगह पाने और "नए आकाओं" को खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं। टैगोर का सबसे तीखा तंज तब सामने आया जब उन्होंने कहा, "जयचंदों के 2026 बैच में आपका स्वागत है।" इस टिप्पणी ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया और कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान को खुलकर सामने ला दिया।

टैगोर यहीं नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि इस तथाकथित समूह में वे लोग शामिल हैं जो आज मोदी सरकार में मंत्री हैं, कुछ ऐसे सांसद हैं जिन्होंने दल बदला और कुछ ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंच चुके हैं। उनके मुताबिक, ऐसे लोग कांग्रेस की विचारधारा या मूल्यों से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होकर बयान दे रहे हैं।

अपने जवाब में मणिकम टैगोर ने राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा और उनके प्रयासों को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे अभियानों के जरिए राहुल गांधी ने देश में नफरत की राजनीति के खिलाफ प्रेम, समावेशन और सामाजिक न्याय की बात रखी। टैगोर के अनुसार, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का 240 सीटों तक पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी के नेतृत्व ने पार्टी को नई ऊर्जा दी और जनता के बीच भरोसा कायम किया।

सूचना

हमारे सभी पाठकों एवं शुभचिंतकों को सूचित किया जाता है कि 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा कार्यालय बंद रहेगा। अतः 27 जनवरी 2026 का अंक प्रकाशित नहीं किया जाएगा।, आगामी अंक 28 जनवरी, 2026 बुधवार से यथाावत अंक प्रकाशित होंगे।

-सम्पादक

गुवाहाटी में अभिषेक शर्मा का महाविस्फोट, न्यूजीलैंड ध्वस्त, भारत ने टी20 सीरीज पर जमाया कब्जा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के नए आक्रामक चेहरे अभिषेक शर्मा ने गुवाहाटी के बारासापारा क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा तूफान मचाया कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम देखते ही देखते मुकाबले से बाहर हो गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने केवल 10 ओवर में 154 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया और 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली। पहले दो मुकाबले जीत चुकी भारतीय टीम के लिए यह लगातार तीसरी जीत रही, जिसने सीरीज में भारत की बादशाहत पर अंतिम मुहर लगा दी।

इस मुकाबले में भारत की जीत सिर्फ स्कोरकार्ड की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस आत्मविश्वास और आक्रामक सोच का प्रतीक थी, जिसके साथ टीम इंडिया अब टी20 क्रिकेट खेल रही है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को भले ही पहले ही ओवर में संजू सैमसन के रूप में झटका लगा हो, लेकिन इसके बाद जो बल्लेबाजी देखने को मिली, उसने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। मैट हेनरी की गेंद पर संजू सैमसन का बोल्ड होना न्यूजीलैंड के लिए राहत की बात हो सकती थी, लेकिन यह राहत कुछ ही मिनटों में पूरी तरह खत्म हो गई।

इसके बाद ईशान किशन ने अपने चिर-परिचित अंदाज में मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। किशन ने महज कुछ गेंदों में ही मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। उनकी 28 रनों की पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जिसने पावरप्ले के भीतर ही भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। चौथे ओवर में ईशान किशन के आउट होने तक भारत का स्कोर 50 के पार जा चुका था और न्यूजीलैंड की रणनीति पूरी तरह बिखर चुकी थी।

इसके बाद मैदान पर आए अभिषेक शर्मा और फिर जो हुआ, वह लंबे समय तक याद किया जाएगा। अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और पहली ही गेंद से आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया और देखते ही देखते भारत को 100 रन के पार पहुंचा दिया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, टाइमिंग और ताकत का अद्भुत मेल देखने को मिला। हर शॉट ऐसा लग रहा था मानो गेंदबाज की मेहनत पर करारा तमाचा हो। अभिषेक शर्मा ने नाबाद 68 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनके बल्ले से निकली हर गेंद स्टेडियम में बैठे दर्शकों के जोश को और ऊंचा ले जा रही थी।

अभिषेक के साथ सूर्यकुमार यादव ने भी अपने अंदाज में शो को यादगार बना दिया। सूर्या ने बिना किसी दबाव के बल्लेबाजी की और नाबाद 57 रन बनाकर टीम को जीत की दहलीज पार कराई। उनकी पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। खास बात यह रही कि सूर्यकुमार और अभिषेक के बीच तालमेल इतना शानदार था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज सिर्फ मूकदर्शक बनकर रह गए। भारत ने मात्र 10 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया, जो टी20 क्रिकेट में किसी भी मजबूत टीम के खिलाफ एक बड़ा बयान माना जाता है।

इससे पहले न्यूजीलैंड की पारी भी भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा, जब हर्षित राणा ने डेवोन कॉन्वे को आउट किया और हार्दिक पंड्या ने शानदार कैच लपका। इसके बाद रचिन रवींद्र और टिम सेफर्ट भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। पावरप्ले के भीतर ही न्यूजीलैंड के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जिससे टीम दबाव में आ गई।

संपादकीय

तेल की कमी नहीं, एक अनकहा वरदान

हमारी आदत है हर उस चीज़ को कोसने की जो हमारे पास नहीं है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय सोच तक, शिकायत हमारी स्थायी मुद्रा बन चुकी है। पड़ोसी के पास कुछ बेहतर हो तो जलन, और किसी दूसरे देश के पास कोई संसाधन हो तो ईर्ष्या। खासकर जब बात तेल की आती है, तो यह भावना और भी तीखी हो जाती है। अक्सर कहा जाता है कि काश हमारे देश के पास भी खाड़ी देशों जैसा अथाह तेल भंडार होता। तब हमें महंगा पेट्रोल-डीजल नहीं खरीदना पड़ता, तब हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा मजबूत होती, तब हम भी अमीर देशों की कतार में खड़े होते। लेकिन इस अधूरी सोच में हम यह भूल जाते हैं कि तेल सिर्फ संपन्नता नहीं लाता, वह अपने साथ खतरे, साजिशें, युद्ध और तबाही का पूरा पैकेज भी लेकर आता है।

आज की दुनिया में तेल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति का सबसे संवेदनशील बिंदु है। जहां तेल है, वहां महाशक्तियों की नजरें गड़ी रहती हैं। वहां की सरकारें केवल अपने नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि बाहर बैठे ताकतवर देशों के हिसाब से फैसले लेने को मजबूर होती हैं। इराक, लीबिया, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों के उदाहरण सामने हैं, जिन्होंने तेल के कारण ही दुनिया की राजनीति का सबसे कठोर चेहरा देखा। इन देशों के पास अपार प्राकृतिक संपदा थी, लेकिन उसी संपदा ने उन्हें कभी चैन से सांस नहीं लेने दी। इराक में सद्दाम हुसैन को कभी अमेरिका का दोस्त माना गया, तो कभी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन। जब तक वह अमेरिकी हितों के मुताबिक चलता रहा, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्वतंत्र नीति अपनाने की कोशिश की, उस पर जनसंहार के हथियार रखने का आरोप लगा दिया गया। पूरी दुनिया को डराया गया, युद्ध थोपा गया और एक समृद्ध देश को खंडहर में बदल दिया गया। बाद में यह साफ हो गया कि जनसंहार के हथियारों का आरोप झूठा था, लेकिन तब तक इराक की कीमत उसके लाखों नागरिक चुका चुके थे। लीबिया में गद्दाफी को तानाशाह कहा गया। लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर हस्तक्षेप हुआ। परिणाम यह हुआ कि आज लीबिया एक स्थिर देश नहीं रहा, बल्कि हथियारबंद गुटों में बंटा हुआ अराजक क्षेत्र बन गया है। वेनेजुएला में मादुरो पर ड्रग तस्करी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, वहां की अर्थव्यवस्था को जानबूझकर कमजोर किया गया। वजह वही पुरानी थी—तेल और ऐसी सरकार जो बाहरी दबावों के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। अब अगर हम कल्पना करें कि हमारे देश के पास भी ऐसे विशाल तेल भंडार होते, तो क्या स्थिति अलग होती? शायद नहीं। तब हमारे यहां भी किसी न किसी बहाने से दबाव बनाया जाता। कभी कहा जाता कि यहां लोकतंत्र खतरे में है, कभी मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया जाता, कभी यह आरोप लगाया जाता कि हम गलत देशों से दोस्ती कर रहे हैं। और अगर इन आरोपों से बात नहीं बनती, तो सीधी धमकी—प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई।

आज भी अमेरिका और पश्चिमी देश हम पर दबाव डालते हैं, लेकिन उनकी सीमाएं तय हैं। वे व्यापार, टैरिफ और कूटनीतिक दबाव तक ही बात रखते हैं। युद्ध की भाषा वे खुलकर नहीं बोलते। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे पास वह संसाधन नहीं है, जिसके लिए वे जान की बाजी लगाने को तैयार हों। तेल होता, तो शायद हमारी संप्रभुता कहीं ज्यादा खतरे में होती। इतिहास गवाह है कि तेल वाले देशों में तख्तापलट कोई असामान्य घटना नहीं है। वहां की राजनीति अक्सर अस्थिर रहती है। सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि साजिशों और हस्तक्षेपों से होता है। जनता का भला पीछे छूट जाता है, और सत्ता की लड़ाई आगे आ जाती है। विकास के नाम पर मिलने वाला पैसा हथियारों, सुरक्षा और युद्ध में खर्च हो जाता है। आम नागरिक के हिस्से में गरीबी, डर और अनिश्चित भविष्य आता है।

हम यह भी भूल जाते हैं कि तेल न होने की मजबूरी ने हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सोचने पर मजबूर किया। हमने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दिया, विज्ञान और तकनीक में निवेश किया, शिक्षा और सेवा क्षेत्र को आगे बढ़ाया। अंतरिक्ष, सूचना तकनीक और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में हमने अपनी अलग पहचान बनाई। अगर हमारे पास आसानी से मिलने वाला तेल होता, तो शायद हम भी उसी पर निर्भर रह जाते और बाकी क्षेत्रों में इतना विकास नहीं कर पाते। तेल कई देशों के लिए वरदान कम और अभिशाप ज्यादा साबित हुआ है। उसने कुछ लोगों को बेहद अमीर बनाया, लेकिन पूरे समाज को स्थिरता नहीं दे सका।

दुनिया को गुमराह ही किया दावोस में ट्रम्प ने

> "दावोस में ट्रंप ने एक घंटे से ज़्यादा लंबा भाषण दिया। ट्रंप ने कई ऐसे दावे किए, जो या तो झूठे थे, या गुमराह करने वाले।

स्वि ट्ज़रलैंड के दावोस में 19 जनवरी से आरम्भ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की 56वीं वार्षिक बैठक का समापन 23 जनवरी को हो चुका है। वहां ट्रम्प गए, पीएम मोदी उनसे रूबरू होने नहीं गए। इस बार की वार्षिक बैठक का थीम, 'ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग' रखा गया है। लेकिन इस डायलॉग का क्या हासिल हुआ? जो बिज़नेस लीडर, नेता-नौकरशाह-अर्थशास्त्री-मीडियाकर्मी यहां आये, उससे उनके देशों या दुनिया को क्या लाभ मिला? इस बात पर कम ही बहस होती है।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) एक अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक है, जो वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शासन प्रमुखों, बिजनेस लीडर्स, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाता है। डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय जेनेवा के कोलोग्नी में स्थित है। इसकी स्थापना 24 जनवरी, 1971 को जर्मन मूल के क्लाउस श्वाब द्वारा की गई थी, जो जेनेवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इसके संस्थापक क्लाउस श्वाब, दशकों तक इसके अध्यक्ष बने रहे। श्वाब ने अप्रैल 2025 में प्रबंधन पर उठे सवाल, और आंतरिक जांच के बीच अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। जांच में श्वाब और उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिली, लेकिन श्वाब ने यह कहते हुए दोबारा ज्वाइन करने से मना किया, कि डब्ल्यूईएफ में वातावरण विषाक्त हो चुका है।

रफ्ता-रफ्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की गंभीरता कम होती जा रही है। बल्कि, इसे 'हाई-प्रोफ़ाइल पिकनिक स्पॉट' की नज़रों से देखा जाने लगा है। आलोचकों का तर्क यह भी है, कि यह मंच, धनी देशों और बड़ी कंपनियों को विशेषाधिकार देता है। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक सैमुअल पी. हंटिंगटन ने इस मंच को 'अभिजात वर्ग के लिए एक मिलन स्थल' के रूप में वर्णित किया, और एक शब्द गढ़ा 'दावोस मैन'। कई वैसे पत्रकार, जिन्हें आर्थिक समझ नहीं है, वो भी 'ग्लोबल जर्नलिस्ट' के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराने दावोस पहुंच जाते हैं। द स्विस टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सालाना बैठक का वेन्यू, दावोस से कहीं और रखने पर भी विचार किया गया है। दावोस में भीड़ को देखकर स्विस नागरिक असहज होने लगे हैं। आमतौर पर डब्ल्यूईएफ में वैश्विक आर्थिक रुझान, भू-राजनीति, जलवायु नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और तकनीकी परिवर्तन पर पैनल चर्चाओं के साथ-साथ छोटी कार्यशालाएं, और गुप्त बैठकें शामिल होती हैं। लेकिन इसका ढब धीरे-धीरे बदलता चला गया। आलोचकों का कहना है, कि दावोस में बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, मगर दुनिया में बढ़ती असमानता को ठीक करने, और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए काम नहीं के बराबर होता है।

इस बार लगभग 400 टॉप पॉलिटिकल लीडर, जिनमें 60 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख शामिल हैं, और दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के लगभग 850 चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ने हिस्सा लिया। दावोस में ईरान की उपस्थिति नहीं थी, इस्राइल के राष्ट्रपति इशाक हर्ज़ोग ज़रूर आये। इस साल जियोपॉलिटिकल माहौल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने ग्रीनलैंड पर कब्ज़े की कोशिश को लेकर नए टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी को 'ब्लैकमेल' कहा है। वेनेज़ुएला, ग्रीनलैंड और ईरान जैसे अलग-अलग विषयों पर ट्रंप के बयानों और आक्रामक टैरिफ नीतियों ने दुनिया के सिस्टम को उलट-पुलट कर दिया है, चुनांचे फोरम की बैठक में ट्रंप ही छाए रहे। पांच दिनों में 200 सत्र आहूत किये गए थे, लेकिन ट्रम्प आये, और सारे विमर्श बस्ते में बंद हो गए।

लेकिन, क्या ट्रम्प इस फोरम पर भी दुनिया को गुमराह कर रहे थे? दावोस में ट्रंप ने एक घंटे से ज़्यादा लंबा भाषण दिया। ट्रंप ने कई ऐसे दावे किए, जो या तो झूठे थे, या गुमराह करने वाले। ट्रंप ने बार-बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना की मौजूदगी के बारे में बात की, इसे एक ऐसे इलाके के तौर पर पेश किया, जिसे अमेरिका ने एक बार डेनमार्क को 'वापस' कर दिया था। फैक्ट चेक करने पर पता चलता है, कि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड की रक्षा में मदद की थी, लेकिन वह कभी भी उस इलाके का मालिक नहीं था। न ही अमेरिका ने डेनमार्क को आज़ाद कराने, या 'बचाने' के लिए कोई अलग से सैन्य अभियान चलाया। सच यह है, कि नाज़ी जर्मनी ने अप्रैल, 1940 में डेनमार्क पर कब्ज़ा कर लिया, तो ग्रीनलैंड को कोपेनहेगन में डेनिश सरकार से अलग कर दिया गया था। जर्मनी को ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और उसकी क्रायोलाइट खानों (विमान एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण) का फायदा उठाने से रोकने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वाशिंगटन में डेनमार्क के राजदूत की मंज़ूरी से हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए सैन्य अड्डे, मौसम स्टेशन और हवाई अड्डे स्थापित किए, लेकिन इसकी कानूनी संप्रभुता कभी नहीं बदली। जर्मन सेना और डेनिश नेतृत्व वाली द्वीप गश्ती दल के बीच छिटपुट झड़पें हुईं, लेकिन ग्रीनलैंड पर नाज़ी जर्मनी ने कभी भी पूरी तरह से कब्ज़ा नहीं किया।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद ग्रीनलैंड, डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य गतिविधि जारी रही, खासकर पिटुफिक स्पेस बेस (पहले जिसका नाम थुले एयर बेस था) के निर्माण के साथ। यह मौजूदगी रक्षा समझौतों पर आधारित थी, न कि स्वामित्व के हस्तांतरण पर। नाज़ी जर्मनी ने ग्रीनलैंड को नियंत्रित नहीं किया, और न ही अमेरिका ने इसे जर्मनी से हासिल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार ग्रीनलैंड को 'बर्फ का एक टुकड़ा' कहा, और तर्क दिया कि ग्लोबल सिक्योरिटी के नाम पर अमेरिका को इसे कंट्रोल करना चाहिए।

ग्रीनलैंड, डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है, और अनुच्छेद 5 के तहत नाटो के सामूहिक रक्षा खंड द्वारा संरक्षित है, जिसमें कहा गया है कि यदि एक सदस्य पर हमला हुआ तो उसे सभी नाटो सदस्यों पर हमला माना जाएगा। ट्रंप, अनुच्छेद 5 जैसी 'लक्ष्मण रेखा' से असमंजस में थे। इसी के हवाले से नाटो के यूरोपीय सदस्य देशों की सेनाएं अमेरिकी फ़ोर्स को काउंटर करने के वास्ते तैयार थीं। यदि ऐसा होता, तो नाटो में विभाजन निश्चित था। ट्रम्प ने अपनी धौंस बनाने के लिए कहा, कि ग्रीनलैंड में हम सैनिक कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन उन यूरोपीय देशों को देख लेंगे, जो अमेरिका के विरुद्ध लामबंद हो रहे थे। दरअसल, ट्रंप दुनिया को बताना नहीं चाह रहे थे, कि ग्रीनलैंड समर्थक यूरोपीय देश ईयू में अपने सबसे सख्त ट्रेड टूल, 'बज़ूका' पर विचार करने के लिए लामबंद हो चुके हैं। यह कदम अमेरिकी सामानों और कंपनियों को ईयू के सिंगल मार्केट में पहुंच से रोक सकता था। यूरोपीय संघ के इस क़दम से अमेरिकी बाज़ार में तबाही मच जाती!

प्रेरणा

जब गणराज्य ने जन्म लिया और भारत ने अपनी असली पहचान पाईः अशोक स्तंभ, संविधान और नए राष्ट्र की पूरी दास्तान

26 जनवरी 1950 का दिन भारत के इतिहास में सिर्फ एक संवैधानिक तारीख नहीं था, बल्कि यह उस क्षण का प्रतीक था जब देश ने औपनिवेशिक मानसिकता को पूरी तरह पीछे छोड़कर अपनी आत्मा, अपने विचार और अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन आज़ादी के बाद भी देश का चेहरा, उसकी व्यवस्था और उसकी सरकारी पहचान अब भी ब्रिटिश राज की छाया में थी। सरकारी दस्तावेजों पर ब्रिटिश क्राउन की मुहर, सेना और नौसेना के नामों में 'रॉयल' शब्द, नोटों पर विदेशी राजा की तस्वीर और अदालतों के आदेशों में राजा के नाम का उल्लेख यह याद दिलाते थे कि सत्ता भले बदल गई हो, लेकिन प्रतीक अब भी पुराने ही थे।

इसी विरोधाभास ने संविधान सभा के भीतर एक गहरी बहस को जन्म दिया। सवाल सीधा था—क्या आज़ाद भारत पुराने साम्राज्यवादी प्रतीकों के साथ आगे बढ़ सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके प्रतीकों में बसती है। अगर प्रतीक गुलामी के दौर के रहेंगे, तो सोच भी उसी दौर की बनी रहेगी। सरदार वल्लभभाई पटेल ने इसे और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब तक जनता रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ब्रिटिश शासन के चिन्ह देखती रहेगी, तब तक मानसिक स्वतंत्रता संभव नहीं है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इस पूरी बहस को संवैधानिक और नैतिक आधार दिया। वे चाहते थे कि नए भारत के प्रतीक धर्मनिरपेक्ष हों, तर्कसंगत हों और किसी भी समुदाय या विचारधारा को अलग-थलग न करें।

इसी सोच के साथ यह तय हुआ कि देश को न केवल नया संविधान चाहिए, बल्कि नई पहचान भी चाहिए। इस पहचान के लिए राष्ट्रीय प्रतीक, ध्वज, राष्ट्रगान, मुद्रा और सरकारी मुहरों का स्वरूप बदलना अनिवार्य था। राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर संविधान सभा में कई तरह के सुझाव सामने आए। कुछ लोगों ने धार्मिक चिन्हों का समर्थन किया, किसी ने देवी-देवताओं, गाय या ओम को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने की बात की। कुछ नेताओं ने आधुनिक भारत को दर्शाने के लिए मशीन, फैक्ट्री, बांध या हाथ मिलाते लोगों की आकृति का सुझाव दिया। ताजमहल, धान और गेहूं की बालियां, हल-बैल, हाथी और बरगद जैसे प्रस्ताव भी चर्चा में आए। लेकिन हर सुझाव पर यही प्रश्न खड़ा होता रहा कि क्या यह प्रतीक पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर पाएगा।

आखिरकार सभी की नजर एक ऐसे प्रतीक पर टिक गई, जो न तो किसी एक धर्म से जुड़ा था और न ही किसी राजा या राजवंश की निजी पहचान था। अशोक स्तंभ भारत की उस प्राचीन परंपरा का प्रतीक था, जहां शासन का अर्थ केवल सत्ता नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी था। सम्राट अशोक का शासन भारतीय इतिहास में इसलिए अलग माना जाता है क्योंकि उन्होंने शक्ति के साथ करुणा, युद्ध के बाद शांति और दंड के साथ धर्म को जोड़ा। उनके शिलालेखों में हिंसा का गर्व नहीं, बल्कि नैतिकता और लोककल्याण का संदेश मिलता है। यही मूल्य उस नए भारत के मूल में थे, जो खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करना चाहता था।

नेहरू, पटेल और अंबेडकर इस बात पर सहमत हो गए कि अशोक स्तंभ भारत की प्राचीन सभ्यता और आधुनिक लोकतंत्र के बीच सेतु बन सकता है। यह प्रतीक यह संदेश देता था कि सत्ता कानून के अधीन होगी और शासन सत्य के रास्ते पर चलेगा। इसी भावना के साथ 'सत्यमेव जयते' को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। यह वाक्य केवल एक श्लोक नहीं था, बल्कि यह नए भारत का नैतिक संकल्प था, जो यह घोषित करता था कि अंततः सत्य की ही विजय होगी।

जब यह तय हो गया कि अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक बनेगा, तब उसके स्वरूप और डिजाइन को लेकर भी गहन विचार हुआ। देशभर के कला विद्यालयों और कलाकारों से डिजाइन मंगवाए गए, लेकिन कोई भी डिजाइन पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगा। अंततः यह जिम्मेदारी शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम को सौंपी गई। नंदलाल बोस ने सारनाथ स्थित मूल अशोक स्तंभ से प्रेरणा लेकर एक ऐसी डिजाइन तैयार की, जो सरल भी थी और गरिमामय भी। चार शेर, जो पीठ से पीठ सटाकर चारों दिशाओं की ओर देखते हैं, शक्ति, साहस और सतर्कता का प्रतीक बने। नीचे बने पशु और धर्मचक्र यह दर्शाते हैं कि यह शक्ति नियंत्रण और कानून से बंधी हुई है।

जिस अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपनी पहचान के रूप में अपनाया, उसका इतिहास भी उतना ही रोचक है। सम्राट अशोक ने इसे लगभग 280 ईसा पूर्व बनवाया था। समय के साथ यह स्तंभ टूट गया और मिट्टी में दबकर कहीं खो गया। सदियों बाद जर्मन सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ओर्टेल भारत आए। उन्हें पुरातत्व में गहरी रुचि थी। उन्होंने चीनी यात्रियों ह्वेनसांग और फाहियान के यात्रा-वृत्तांतों का अध्ययन किया, जिनमें सारनाथ का उल्लेख मिलता है। इन्हीं विवरणों के आधार पर 1904–1905 में खुदाई करवाई गई, जिसमें अशोक स्तंभ का शेर वाला ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह सुरक्षित अवस्था में मिला। यह खोज भारत की सांस्कृतिक विरासत को फिर से सामने लाने वाली थी।

संविधान के प्रति राजनीतिक जागरूकता पर्याप्त नहीं, स्वाभिमान के रूप में करना चाहिए स्वीकार

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ब्रिटिश आधिपत्य से स्वाधीनता के समय भारत के नेतृत्व ने भावी पीढ़ियों के शासन-प्रशासन हेतु एक संविधान का निर्माण किया। दो वर्ष, 11 महीने और 18 दिन तक संविधान सभा की बैठकें हुईं। उसके परिणामस्वरूप हमें विश्व का विशालतम संविधान प्राप्त हुआ। नौ दिसंबर 1946 से प्रारंभ कर 26 नवंबर 1949 तक हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक जीवन के विभिन्न आयामों पर वृहद विचार विमर्श किया। उन्होंने विश्व के अनेक विद्यमान संविधानों का भी गहन अध्ययन किया और भारत के संविधान में संसार भर के संविधानों के श्रेष्ठ और स्वीकार्य तत्व सम्मिलित किए गए। इस प्रकार भारत का संविधान ऐसा अभिलेख बन गया जो विश्व की श्रेष्ठतम लोकतांत्रिक संस्थाओं और परंपराओं का सहज समावेश करता है। भारतीय संविधान की निर्मिति में संलग्न लगभग 300 व्यक्तियों की ओर दृष्टिपात करें तो यह ध्यान में आता है कि तत्कालीन भारत की श्रेष्ठतम मेधा, मनीषा, प्रतिभा संविधान सभा में उपलब्ध थी। वह संविधान सभा अनेक विचारधाराओं, क्षेत्रों, मतावलंबियों, भाषा-भाषियों, आजीविकाओं, समुदायों, संप्रदायों, राज-व्यवस्थाओं और रुचियों का प्रतिनिधित्व करती थी। वहां राजनेता, साहित्यकार, लेखक, उपन्यासकार, दार्शनिक, वकील, चिकित्सक, किसान, आदिवासी सभी प्रकार के व्यक्ति थे। उन सबने लगभग प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अनुच्छेद, प्रत्येक संस्था और प्रत्येक नियम-विधि पर गहन और गंभीर वाद विवाद भी किया। इसका ही परिणाम हुआ कि भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में ही अपने दार्शनिक मूल्यों और व्यावहारिक आधार की स्पष्ट उद्घोषणा करता है। वह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का उद्घोष करता है। कालांतर में 1976 में आंतरिक आपातकाल में यहां पंथनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द भी जोड़ दिए गए। यह संविधान भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ-साथ विचार अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास तथा उपासना की स्वतंत्रता तथा स्तर और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह संविधान भारत के नागरिकों में आपसी बंधुता बनाए रखने को कटिबद्ध है। यह भारत की राष्ट्रीय एकता और अक्षुण्णता बनाने के लिए संकल्पित है। भारतीय संविधान अपने चरित्र में कठोरता और नमनीयता के सम्मिश्रण से युक्त है। वह समकालीनता की अपेक्षाओं और परिवर्तनशील युगीन आकांक्षाओं के अनुरूप स्वयं को रूपांतरित करने में सक्षम है। वह अनेक प्रविधानों और उपबंधों के रूप में सामाजिक परिवर्तन का प्रमुखतम संवाहक भी बन गया है। वह भारत के प्रशासनिक नियमन का मुख्यतम स्रोत तथा आधार है। वह देश के सभी राजनीतिक तथा शासकीय संस्थानों का दिशा निर्देशक उपकरण है। वह भारत की सांस्कृतिक परंपरा की रक्षा के भी प्रयास करता है तो आधुनिकता के आग्रहों का भी यथेष्ट सम्मान करता है। भारत का संविधान अपने 395 अनुच्छेदों, 22 भागों तथा 12 अनुसूचियों में भारतीय सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन के अनेक प्रश्नों को संबोधित करता है। भारतीय संविधान ने लगभग सवा सौ संशोधनों के माध्यम से स्वयं को नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला है। भारतवर्ष के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धार्मिक मान्यता आदि के अधिकार संविधान से ही प्राप्त होते हैं। इन मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी संविधान भारतीय न्यायपालिका को प्रदान करता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका इस संविधान की व्याख्या और रक्षा के पुनीत अधिकार से संपन्न है। नागरिकता के प्रश्न भी भारतीय संविधान ही संबोधित करता है। एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की संकल्पना संवैधानिक लोकतंत्र की संरचनात्मक आश्वस्ति बनती है। भारतवर्ष की वित्तीय संरचना, कार्यप्रणाली और व्यवहार के स्वायत्त पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा अंकेक्षण हेतु एक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की व्यवस्था भी संविधान करता है। राज्य अपनी नीति-निर्माण प्रक्रिया में किन मूल्यों तथा सिद्धांतों को ध्यान में रखे - इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं, उपकरणों, अधिकरणों आदि का गठन करते हुए भारतीय संविधान आधुनिक भारत का सर्वप्रमुख नीतिग्रंथ और मार्गदर्शन केंद्र बन गया है। आधुनिक समय में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा के बाद से दसेक वर्षों में भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। गणतंत्र दिवस पर भी हम अपने संविधान निर्माताओं का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। साथ ही इस दिन हम संविधान के प्रति अपने सम्मान और निष्ठा की शपथ भी लेते हैं। परंतु फिर भी प्रायः संविधान को मात्र विधि, न्यायालय, राजनीति विज्ञान तथा राजनीतियों की विषयवस्तु मान लिया जाता है। जबकि सत्य और तथ्य यह है कि हमारे जीवन के लगभग प्रत्येक आयाम को भारतीय संवैधानिक व्यवस्था स्पष्टतः स्पर्श करती है। इसलिए भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता हमारी सामूहिक आवश्यकता है। कतिपय लोगों द्वारा प्रतिदिन 'संविधान पर खतरा', 'संविधान से छल', 'संविधान का विरोध', 'संविधान की धज्जियां' आदि नारे लगाकर भ्रम उत्पन्न किया जाता है। संविधानिक निकायों में संविधान की प्रतियां लहराई जाती हैं। ऐसे में यह जानना अनिवार्य है कि संविधान में वास्तव में क्या लिखा है- यह समझना आवश्यक है। संविधान को वस्तुतः किससे खतरा है, किसने संविधान पर असली हमला किया, कौन संविधान की धज्जियां उड़ाता रहा है, ऐसे प्रश्नों को ठीक से परखना जरूरी है। वास्तव में हमारे अधिकार क्या और कौन-कौन से हैं? हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य क्या हैं? हमारी संवैधानिक संस्थाएं कैसी हैं? हमारे संविधान की व्याख्या कौन करता है और कैसे करता है? इस संविधान का आत्मा क्या है? हमारा संविधान विश्व में श्रेष्ठतम कैसे है? इन सभी प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान यह मानना प्रारंभ करने में है कि यह मेरा संविधान है। मेरा स्वाभिमान है। यह भारत का स्वाभिमान है!

अभियान

महाशिवरात्रि की महिमा और शिवलिंग अभिषेक से बदलता भाग्य

महाशिवरात्रि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का ऐसा पर्व है, जो केवल पूजा-पाठ या व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और उसे संतुलित करने का गहरा अवसर प्रदान करता है। यह वह रात्रि मानी जाती है जब भगवान शिव पूर्ण रूप से जाग्रत होते हैं और सृष्टि की चेतना उनके साथ एक विशेष तालमेल में आ जाती है। शास्त्रों के अनुसार यही वह पावन क्षण है जब महादेव और माता शक्ति का दिव्य मिलन हुआ था, जिससे सृष्टि में सृजन, संरक्षण और संहार का संतुलन स्थापित हुआ। इस कारण महाशिवरात्रि को केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि ऊर्जा, साधना और आत्मिक उन्नति का महापर्व माना गया है। इस वर्ष महाशिवरात्रि अत्यंत शुभ योगों में आ रही है, जिससे इसका आध्यात्मिक प्रभाव और अधिक गहरा माना जा रहा है।

शिवलिंग स्वयं में ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह निराकार और साकार का संगम है, जहां से सृष्टि की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब भक्त महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करता है, तो वह केवल परंपरा का पालन नहीं करता, बल्कि अपने भीतर के विकार, भय, दुख और बाधाओं को शिव तत्व में अर्पित करता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया अभिषेक जन्म-जन्मांतर के पापों का नाश करता है और व्यक्ति के भाग्य में छिपी संभावनाओं को जाग्रत करता है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली प्रत्येक सामग्री का अपना एक गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ है, जो जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

आर्थिक संकट आज के समय की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। मेहनत के बावजूद कर्ज खत्म नहीं होता, आय के स्रोत बाधित रहते हैं और भविष्य को लेकर भय बना रहता है। ऐसे में शास्त्रों में महाशिवरात्रि के दिन गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने का विशेष उल्लेख मिलता है। गन्ना मिठास, निरंतरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि गन्ने का रस चढ़ाने से जीवन में रुकी हुई आर्थिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। यह उपाय केवल धन प्राप्ति का नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और कर्ज मुक्ति की दिशा में भी सहायक माना जाता है।

मानसिक तनाव, अवसाद और शारीरिक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति के लिए महाशिवरात्रि का दिन विशेष संजीवनी की तरह माना गया है। कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा चंद्रमा से जुड़ी हुई है, जो मन का कारक ग्रह माना जाता है। दूध चढ़ाने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे मन को शांति, स्थिरता और सकारात्मकता मिलती है। साथ ही शहद का अभिषेक करने से शरीर और मन दोनों में जमी नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शहद चढ़ाने से पुरानी बीमारियों में राहत मिलती है और व्यक्ति की वाणी में मधुरता आती है, जिससे रिश्तों में सुधार होता है।

प्रकृति से जुड़े तत्व शिव को अत्यंत प्रिय हैं। बिल्व पत्र को तो शिव पूजा का अभिन्न अंग माना गया है। बिल्व पत्र में त्रिदेवों का वास माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति के तीनों ताप—दैहिक, दैविक और भौतिक—शांत होते हैं। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि शमी पत्र भी शिव को अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। शमी पत्र चढ़ाने से शनि दोष में कमी आती है, जीवन में चल रही अड़चनें धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं और भाग्य का साथ मिलने लगता है। बिल्व पत्र को हमेशा उल्टा करके चढ़ाने की परंपरा है और उस पर चंदन से 'ॐ' लिखना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि 'ॐ' स्वयं शिव का बीज मंत्र है और सृष्टि की मूल ध्वनि माना जाता है।

विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में तनाव या रिश्तों में बढ़ती दूरी आज कई लोगों की समस्या बन चुकी है। महाशिवरात्रि पर केसर मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा इसी समस्या से जुड़ी हुई है। केसर पवित्रता, प्रेम और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ इत्र अर्पित करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और रिश्तों में मधुरता आती है। यह उपाय केवल विवाह के लिए नहीं, बल्कि दांपत्य सुख और पारिवारिक शांति के लिए भी प्रभावी माना गया है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि भी अपने आप में एक साधना है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और मन को शांत करके शिव मंदिर जाना चाहिए। शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल, फिर दूध, दही, घी, शहद और अंत में पुनः शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है। यह क्रम पंचतत्वों के संतुलन का प्रतीक है और जीवन में संतुलन स्थापित करने का संदेश देता है। भस्म का तिलक लगाना जीवन की नश्वरता का स्मरण कराता है और अहंकार को दूर करता है। बिना टूटे हुए अक्षत चढ़ाने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति का संकेत माना जाता है, क्योंकि अक्षत पूर्णता और निरंतरता का प्रतीक है।

पूजा के दौरान "ॐ नमः शिवाय" का मन ही मन जप करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यह पंचाक्षरी मंत्र शरीर, मन और आत्मा के पांच स्तरों को शुद्ध करता है। महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण और साधना की रात्रि होती है। कहा जाता है कि इस रात जागकर शिव चालीसा, शिव स्तुति या शिव पुराण का पाठ करने से साधक को विशेष पुण्य प्राप्त होता है और उसकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती है। यह रात्रि केवल जागने की नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर जागने की रात्रि है।

महाशिवरात्रि का वास्तविक उद्देश्य केवल मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्मिक परिवर्तन है। जब व्यक्ति सच्चे भाव से शिवलिंग पर सामग्री अर्पित करता है, तो वह बाहरी उपाय के साथ-साथ आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया भी शुरू करता है। यही कारण है कि इस दिन किए गए उपाय धीरे-धीरे जीवन की दिशा बदलने लगते हैं। शिव कृपा केवल मांगने से नहीं, बल्कि समर्पण और समझ से मिलती है।

इसलिए महाशिवरात्रि को केवल एक पर्व की तरह न मनाएं, बल्कि इसे आत्मचिंतन, साधना और संतुलन का अवसर बनाएं। जब मन श्रद्धा से झुकता है और कर्म शुद्ध होते हैं, तब भाग्य के बंद द्वार स्वयं खुलने लगते हैं। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि शिव बाहर नहीं, भीतर हैं, और जब भीतर का शिव जागता है, तब जीवन स्वयं प्रकाशमय हो जाता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

77वां गणतंत्र पर्व – राज्य महोत्सव : वाव थराद जिला

वाव थराद जिले के औद्योगिक विकास में ऐतिहासिक कदम

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल के करकमलों से गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा 99.23 एकड़ सरकारी भूमि पर स्थापित होने वाली जीआईडीसी औद्योगिक बस्ती का भूमिपूजन

▸▸ विकास की बातें जमीन पर साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है

▸▸ नवगठित वाव थराद जिला विकसित जिलों की पंक्ति में शीघ्रता से आए, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

▸▸ दूधवा जीआईडीसी कार्यरत होने से उत्पादन के मूल्यवर्धन द्वारा 'वोकल फॉर लोकल' को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे : मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल

▸▸ दूधवा जीआईडीसी का निर्माण होने पर सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक प्रगति के नवीन द्वार खुलेंगे : विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी

(जीएनएस)। गांधीनगर, 25 जनवरी : 77वें गणतंत्र पर्व का राज्य-स्तरीय समारोह नवगठित वाव थराद जिले में आयोजित किया जा रहा है । इस आयोजन के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल के करकमलों से रविवार को इस जिले के दूधवा में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा 99.23 एकड़ सरकारी भूमि पर निर्मित होने वाली औद्योगिक बस्ती का भूमिपूजन गौरवपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि जीआईडीसी के निर्माण से नए जिले के विकास को गति मिलेगी, साथ ही 'वोकल फॉर लोकल' का प्रधानमंत्री का लक्ष्य भी साकार होगा। इतना ही नहीं, सीमावर्ती जिले में युवाओं को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास सही अर्थों में जमीन पर साकार हो, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। प्रधानमंत्री ने सड़क- मार्ग, पेयजल, स्वास्थ्य सहित प्रत्येक क्षेत्र में देश के नागरिकों की भलाई की चिंता की है और सुदूरवर्ती व्यक्ति को केंद्र में रखकर विकासोन्मुखी योजनाएं लागू की हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नवगठित वाव थराद जिले का विकास भी अन्य विकसित जिलों के समान तीव्र गति से हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

श्री पटेल ने आगे कहा कि इस क्षेत्र में कृषि के लिए तालाब, ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक पद्धतियों का व्यापक उपयोग हो रहा है, यह आनंद की बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दूरदर्शी नेता हैं, क्योंकि आज पानी उपलब्ध है तो भविष्य में भी पानी उपलब्ध रहे; इसके लिए उन्होंने पूर्व योजना बनाई है। 'कैच द रेन' अभियान अंतर्गत अतिरिक्त वर्षा जल के संग्रह के लिए देशभर में आयोजनबद्ध अभियान चलाया गया है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक समान पुण्य कार्य है।

उन्होंने जोड़ा कि खेती के आलावा उत्पादन के मूल्यवर्धन पर भी विचार किया गया है। वैल्यू एडिशन के लिए छोटे-बड़े उद्योग स्थापित हो सकें और 'वोकल फॉर लोकल' से 'लोकल टू ग्लोबल' का लक्ष्य साकार हो; इसके लिए आने वाले दिनों में यह जीआईडीसी एस्टेट महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2003 में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप आज एमएसएमई की संख्या 1 लाख 68 हजार से बढ़कर 27 लाख से अधिक हो गई है। इस मजबूत आधार के कारण देश सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और आज हम सभी 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

इस अवसर पर गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक प्रगति के नए द्वार खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का किसान मेहनती है। अनार हो या अन्य फसल; यहां का उत्पादन अब तक प्रोसेसिंग के लिए राजकोट, अहमदाबाद या अन्य राज्यों में जाता था। अब दूधवा में जीआईडीसी बनने से कृषि उत्पादों का 'वैल्यू एडिशन' यहीं होगा, जिससे किसानों की आय दोगुनी होगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री ने केवल एक वर्ष की अल्प अवधि में जीआईडीसी को मंजूरी दी और आज उसका भूमिपूजन भी संपन्न कराया। साथ ही, प्रथम चरण के लिए 15 से 16 करोड़ रुपए के सड़क और बुनियादी सुविधाओं के कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

श्री शंकरभाई चौधरी ने भावुक स्वर में कहा कि मुख्यमंत्री ने इस सीमावर्ती क्षेत्र को नया जिला बनाकर प्रशासनिक सुविधा प्रदान की है। इतना ही नहीं, इस वर्ष यहां गणतंत्र पर्व की राज्य स्तरीय समारोह एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम भी आयोजित कर विकास को गति दी है।

भूतकाल की बाढ़ की घटनाओं को याद करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि जब यह क्षेत्र संकट में था, तब मुख्यमंत्री श्री स्वयं मौके पर पहुंचे थे, लोगों का दुख साझा किया था और उदारतापूर्वक सहायता प्रदान की थी। कृषि फसलों को हुए नुकसान के मामलों में भी सरकार ने सदैव संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है।

इस अवसर पर खादी एवं कुटीर ग्राम उद्योग राज्य मंत्री श्री स्वरूपजी ठाकोर, दियोदर विधायक श्री केशाजी चौहान, जिला प्रभारी सचिव श्री नागराजन, जीआईडीसी की प्रबंध निदेशक सुश्री प्रवीणा डी. के., कार्यकारी निदेशक श्री भरत जोशी, जिला कलेक्टर श्री जे. एस. प्रजापति सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी एवं नागरिक उपस्थित रहे।

नवगठित वाव थराद जिले को मिलेगा अत्याधुनिक जिला सेवा सदन

▸▸ 77वें गणतंत्र पर्व की राज्य स्तरीय समारोह का पहली बार मेजबान बने जिले के विकास की नई दिशा

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से 39 एकड़ में बनने वाले जिला सेवा सदन का भूमि पूजन किया

▸▸ विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी एवं राज्य मंत्री श्री स्वरूपजी ठाकोर की प्रेरक उपस्थिति

▸▸ जिले के नागरिकों को एक ही स्थान पर सरकार के विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध होंगी

▸▸ नवगठित वाव थराद जिले को आगामी दिनों में एक नया अत्याधुनिक जिला सेवा सदन मिलेगा

▸▸ यह नया निर्माण होने वाला सेवा सदन जिले के सर्वांगीण विकास को नई दिशा प्रदान करेगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : 77वें गणतंत्र पर्व की राज्य स्तरीय समारोह का पहली बार मेजबान बने वाव थराद जिले में महत्वपूर्ण विकास कार्य का शुभारंभ किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने थराद में लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से 39 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले जिला सेवा सदन का भूमिपूजन एवं शिलान्यास (तख्ती अनावरण) संपन्न किया।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी तथा राज्य मंत्री श्री स्वरूपजी ठाकोर उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुशासन के दृष्टिकोण के अनुरूप नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर सरलता से उपलब्ध हों, इस उद्देश्य से जिला मुख्यालयों पर जिला सेवा सदन के निर्माण का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए नवगठित वाव थराद जिले में आधुनिक सेवा सदन का निर्माण किया जाएगा।

इस नए जिला सेवा सदन में जिला कलेक्टर कार्यालय सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के 30 से अधिक जिला स्तरीय कार्यालय कार्यरत किए जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप जिले के नागरिकों को एक ही स्थान से सरकार के विभिन्न विभागों की सेवाएं सरलता से प्राप्त होंगी तथा उनके समय और संसाधनों की बचत होगी, साथ ही प्रशासनिक कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

वाव थराद जिले के इस सेवा सदन का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग के मानकों के अनुसार किया जाएगा। इसमें सोलर रूफ टॉप, वर्षा जल संचय की व्यवस्था, विशाल मीटिंग हॉल, अत्याधुनिक लिफ्ट तथा बेसमेंट पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

इस अवसर पर दियोदर विधायक श्री केशाजी चौहान, जिला प्रभारी सचिव श्री नागराजन, जिला कलेक्टर श्री जे. एस. प्रजापति, जिला विकास अधिकारी श्री कार्तिक जीवाणी,सड़क एवं भवन विभाग के सचिव श्री पी. आर. पटेलिया, विशेष सचिव श्री जे. ए. गांधी, अधीक्षण अभियंता श्री एल. डी. चौधरी, कार्यपालक अभियंता श्री तेजस मांगुकिया सहित अन्य पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

अहमदाबाद–विरमगाम सेक्शन के बीच ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित

(जीएनएस)। अहमदाबाद–विरमगाम सेक्शन के साबरमती ए केबिन और साबरमती स्टेशन के बीच ऑटोमैटिक सिगनलिंग सिस्टम चालू करने के लिए 27 जनवरी, 2026 को 08:30 बजे से 20:30 बजे तक 12 घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 27 जनवरी, 2026 को प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:-

शॉर्ट टर्मिनेट होने वाली ट्रेनें:-

1. ट्रेन संख्या 20901/20902 मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर केपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस अहमदाबाद में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। इसलिए, यह ट्रेन अहमदाबाद और गांधीनगर केपिटल स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

निरस्त होने वाली ट्रेनें:-

1. ट्रेन संख्या 20959 वलसाड–वडनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 20960 वडनगर–वलसाड सुपरफास्ट एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें:-

1. ट्रेन संख्या 12216 बांद्रा टर्मिनस–दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ को परिवर्तित मार्ग वाया अहमदाबाद–साबरमती ए केबिन–चांदलोडिया–खोडियार स्टेशनों के रास्ते चलाया जाएगा।

2. ट्रेन संख्या 14807 जोधपुर–दादर एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग वाया खोडियार–चांदलोडिया–साबरमती ए केबिन–अहमदाबाद स्टेशनों के रास्ते चलाया जाएगा और इस ट्रेन का साबरमती जंक्शन पर अतिरिक्त ठहराव होगा। इसलिए, यह ट्रेन साबरमती ब्रॉड गेज स्टेशन पर नहीं रुकेगी।

भावनगर टर्मिनस यार्ड में पिट लाइन के कार्य हेतु लिए गए ब्लॉक की अवधि को बढ़ा दिया गया है जिसके कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के भावनगर टर्मिनस स्टेशन यार्ड में पिट लाइन संख्या–2 के मरम्मत कार्य हेतु ब्लॉक 45 दिनों का ब्लॉक लिया गया था, जिसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। इस कारण कुछ ट्रेनें 26 और 27 जनवरी, 2026 को भी प्रभावित रहेंगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार प्रभावित ट्रेनों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

निरस्त (Cancel) की जाने वाली ट्रेनें

1. ट्रेन नंबर 59228/59233 भावनगर–सुरेंद्रनगर–भावनगर पैसेन्जर 26.01.2026 को निरस्त रहेगी।
2. ट्रेन नंबर 59267/59268 भावनगर–पालिताना–भावनगर पैसेन्जर 26.01.2026 को निरस्त रहेगी।
3. ट्रेन नंबर 59269/59270 भावनगर–पालिताना–भावनगर पैसेन्जर 26.01.2026 को निरस्त रहेगी।
4. ट्रेन नंबर 59230 भावनगर–बोटाद पैसेन्जर 26.01.2026 को निरस्त रहेगी।
5. ट्रेन नंबर 59229 बोटाद-भावनगर पैसेन्जर 27.01.2026 को निरस्त रहेगी।
6. ट्रेन नंबर 59204/59271 भावनगर–बोटाद–भावनगर पैसेन्जर 26.01.2026 को निरस्त रहेगी।
7. ट्रेन नंबर 59235 धोला-महुवा पैसेन्जर 26.01.2026 को निरस्त रहेगी।
8. ट्रेन नंबर 59236 महुवा-धोला पैसेन्जर 27.01.2026 को निरस्त रहेगी।
9. ट्रेन नंबर 09529/09530 धोला–भावनगर–धोला टीओडी स्पेशल 26.01.2026 को निरस्त रहेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पूर्व संबंधित स्टेशन अथवा रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in से अद्यतन जानकारी प्राप्त करें।

गणतंत्र पर्व की पूर्व संध्या पर थराद में 'सरहद का साद - नूतन वाव थराद' मल्टीमीडिया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

▸▸ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा उल्लेखनीय योगदान देने वाले जिले की 16 विशिष्ट व्यक्तियों का राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा सम्मान

▸▸ वाव थराद जिले को 207 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट

▸▸ मुख्यमंत्री के करकमलों से जिला कलेक्टर एवं जिला विकास अधिकारी को विकास कार्यों के लिए 2.50 करोड़ रुपए के चेक प्रदान

राज्यपाल आचार्य देवव्रत

▸▸ राज्यपाल ने गणतंत्र पर्व पर वाव थराद की जनता की शालीनता और संस्कारों की सराहना की

▸▸ राज्यपाल ने जिलावासियों से शिक्षा, संस्कार एवं प्राकृतिक खेती का संदेश देते हुए वाव थराद को 'मॉडल जिला' बनाने का आह्वान किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ मुख्यमंत्री के करकमलों से जिला कलेक्टर एवं जिला विकास अधिकारी को विकास कार्यों के लिए 2.50 करोड़ रुपए के चेक प्रदान

▸▸ वाव थराद जिला सौर ऊर्जा में अग्रणी बने, यह सरकार का दृढ़ संकल्प

विकसित वाव थराद के रोडमैप द्वारा विकसित गुजरात एवं विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान

अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी

▸▸ जीआईडीसी के माध्यम से स्थानीय किसान उद्योगपति बनेंगे और कृषि उत्पादों के निर्यात को गति मिलेगी

▸▸ नए वाव थराद जिले को भेंट देने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र के लोग मुख्यमंत्री के ऋणी रहेंगे

(जीएनएस)। गांधीनगर : 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की राज्य स्तरीय समारोह श्रंखला अंतर्गत रविवार को नवगठित वाव थराद जिले में गणतंत्र पर्व की पूर्व संध्या पर थराद के मलुपुर में 'सरहद का साद - नूतन वाव -थराद' मल्टीमीडिया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि वाव थराद नया जिला बनने के बाद पहली बार यहां गणतंत्र पर्व का इतनी भव्य एवं दिव्य रूप से उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए समस्त जिलावासी अभिनंदन के पात्र हैं।

राज्यपाल ने कहा, "गुजरात में राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मैंने अनेक भव्य कार्यक्रम देखे हैं, परंतु यहां की जनता में जो शालीनता, सभ्यता और सरलता दिखाई देती है, वैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। यहां के लोग अत्यंत भले और संस्कारी हैं।" उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा नवगठित जिले के लिए घोषित विभिन्न विकास कार्यों एवं अनुदान की सराहना करते हुए कहा कि नए जिले के गठन से इस क्षेत्र के विकास को और अधिक गति मिलेगी।

राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी के प्रयासों और बनास डेयरी के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र को हरा-भरा बनाने में सहकारी गतिविधियों का बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने माता-पिता से अपील की कि बेटा- बेटी के शिक्षा में भेदभाव करे बिना बच्चों को उच्च शिक्षा दें और उन्हें व्यसन मुक्त व संस्कारवान बनाएं, ताकि वे परिवार और देश का गौरव बढ़ा सकें।

पशुपालन से जुड़े इस क्षेत्र के किसानों को राज्यपाल ने 'जहर-मुक्त खेती' अर्थात प्राकृतिक खेती अपनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, "यदि आप प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे तो पर्यावरण, धरती माता और गौ माता की रक्षा होगी, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा और भूमिगत जलस्तर भी ऊंचा आएगा।" उन्होंने जिलावासियों से वाव थराद जिले को प्राकृतिक खेती में 'मॉडल जिला' बनाने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' श्लोक के साथ सभी के उत्तम स्वास्थ्य एवं सुख-समृद्धि की मंगलकामना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि आज नवगठित वाव थराद जिले में 77वें गणतंत्र पर्व का पहला राज्य स्तरीय ध्वजवंदन समारोह आयोजित हो रहा है, जो मेरे लिए गर्व और आनंद का क्षण है। सुबह से जिले की जनता में जो उत्साह, उमंग और देशभक्ति का वातावरण देखने को मिल रहा है, वह इस ऐतिहासिक क्षण को और भी यादगार बना रहा है। इस पावन अवसर पर उन्होंने सभी को 77वें गणतंत्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1947 में हमने अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त की और उसके बाद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान ने हमें लोकतंत्र का मार्ग दिखाया और गणतंत्र पर्व मनाने का अधिकार दिया। गणतंत्र पर्व 140 करोड़ भारतीयों के लोकतंत्र पर अटूट विश्वास का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' पूरे वर्ष मनाने का संकल्प लिया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास, संस्कृति और विरासत से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'राष्ट्रहित प्रथम' की भावना से राष्ट्रीय पर्वों को सीमित ढांचे से बाहर निकालकर राज्य के विभिन्न जिलों में मनाने की परंपरा प्रारंभ की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाव थराद जिले में आयोजित यह पहला राज्य स्तरीय समारोह सीमावर्ती क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के संकल्प का जीवंत उदाहरण है।

उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा यह जिला सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1965 तथा 1971 के युद्ध के दौरान यहां की जनता ने जो शौर्य और साहस दिखाया, वह आज भी सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। इस अवसर पर उन्होंने रणछोड़ पगी जैसे अद्वितीय देशभक्तों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया 'ईज ऑफ लिविंग' का मंत्र आज वाव थराद में साकार होता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री ने जिलावासियों को जानकारी देते हुए कहा कि वाव थराद जिले में ग्रामीण पंचायत विभाग के विकास के लिए 59 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। किसानों को फसल क्षति के बदले 395 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।

जल विकास कार्यों के लिए 2500 करोड़ रुपए की विशेष परियोजना लागू की गई है। उन्होंने आगे कहा कि थराद नगरपालिका को ए-ग्रेड में उन्नत किया गया है, जिससे अब उसे वार्षिक 12 करोड़ रुपए की ग्रांट प्राप्त होगा। डबल इंजन सरकार में विकास की गति भी डबल हुई है और कौशल भी डबल हुआ है। राधा नेसडा और मसाली गांवों ने जिले को ग्रीन एनर्जी में विशिष्ट पहचान दिलाई है। आगामी समय में वाव थराद जिला सोलर एनर्जी में अग्रणी बने, यह सरकार का दृढ़ संकल्प है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र पर्व के मेजबान बने वाव थराद जिले को आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत संरचना की दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ विकसित वाव थराद के रोडमैप द्वारा विकसित गुजरात और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का मुख्यमंत्री ने आह्वान किया।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने कहा कि वाव थराद जिले के गठन के मात्र साढ़े तीन महीनों में कलेक्टर कार्यालय के भूमिपूजन के साथ 207 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होना ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जीआईडीसी के माध्यम से स्थानीय किसान उद्योगपति बनें और कृषि उत्पादों के निर्यात को गति मिले, ऐसा दूरदर्शी दृष्टिकोण साकार किया है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि नए वाव थराद जिले की भेंट देने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र के लोग मुख्यमंत्री के ऋणी रहेंगे।

अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने कहा कि वाव थराद क्षेत्र की जल समस्या के स्थायी समाधान के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नर्मदा जल को तालाबों तक पहुंचाने की मंजूरी से क्षेत्र की कायापलट हो जाएगी । उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की देशभक्ति की सराहना करते हुए, 77वें प्रजासत्ताक पर्व के अवसर पर राज्य स्तरीय ध्वजवंदन कार्यक्रम के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा उल्लेखनीय योगदान देने वाले जिले की 16 विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान किया गया, जो जिले के लिए गौरव का क्षण बना । इस अवसर पर 'विकास, विरासत और विश्वास' का प्रतीक वाव थराद पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

जिला कलेक्टर श्री जे.एस. प्रजापति ने स्वागत भाषण में सभी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर एवं जिला विकास अधिकारी को विकास कार्यों के लिए 2.50 करोड़ रुपए के चेक प्रदान किए।

इस अवसर पर 23.23 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए 6 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 184.32 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 19 नए कार्यों का शिलान्यास कर जिले को कुल 207 करोड़ रुपए की विकास भेंट दी गई।

राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में नृत्य, संगीत और नाटक के त्रिवेणी संगम के माध्यम से नवगठित वाव थराद जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और सीमावर्ती क्षेत्र की देशभक्ति भावना का जीवंत और भावपूर्ण प्रदर्शन किया गया। आधुनिक मल्टीमीडिया प्रस्तुति के साथ यह कार्यक्रम दर्शकों के लिए स्मरणीय और प्रेरणादायक अनुभव बना।

इस अवसर पर राज्य स्तरीय मंत्री श्री स्वरूपजी ठाकोर, विधायकगण श्री केशाजी चौहान, श्री मावजीभाई देसाई, श्री लविंगजी ठाकोर, अग्रणी श्री कीर्तिसिंह वाघेला, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव श्री मनोजकुमार दास, अपर मुख्य सचिव डॉ. अंजु शर्मा, अपर सचिव श्री संजीव कुमार, पुलिस महानिदेशक के.एल.एन. राव, प्रभारी सचिव श्री एम. नागराजन सहित कई अधिकारी एवं नागरिक उपस्थित रहे।

आफिसर्स स्पोर्ट्स मीट में वडोदरा मंडल ने जीती कलचरल एवं स्पोर्ट्स शील्ड,39 पदक जीतकर खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने पश्चिम रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा मुंबई में आयोजित 45 वीं ऑफिसर्स स्पोर्ट मीट में प्रधान कार्यालय एवं सभी मंडलों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पूनूस ट्रॉफी को एक बार फ़िर से जीत लिया है। स्पोर्ट्स प्रतिस्पर्धा में वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने एथेलेटिक्स के सिंगल एवं रिले रन और पश्चिम रेलवे महिला कल्याण मंडल के वडोदरा मंडल की अध्यक्षा श्रीमती कविता भडके ने एथेलेटिक्स के महिला वर्ग में सिंगल एवं रिले रन में पदक जीतकर मंडल के अन्य खिलाड़िओं को स्पोर्ट्स मीट में पदक जीतने को प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया। वडोदरा मंडल के खिलाड़िओं ने इस मीट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 25 गोल्ड और 14 सिल्वर सहित कुल 39 मैडल जीते। पश्चिम रेलवे एवं मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके को शील्डें एवं खिलाड़ी विजेताओं को मेडल प्रदान किये। स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में वडोदरा मंडल के खिलाड़िओं ने पुरुष वर्ग में टेबल टेनिस सिंगल, डबल एवं मिक्स,बैडमिंटन सिंगल एवं मिक्स, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, स्लो साइकिल, स्क्वैश सिंगल एवं डबल में गोल्ड मैडल जीता तो वही महिला वर्ग में टेबल टेनिस, स्लो साइकिल, रन फॉर रन, बैंडमिंटन, एथेलिटिक्स में गोल्ड जीता। पुरुषों की टीम ने वॉलीवॉल एवं महिलाओं की टीम ने बॉक्स क्रिकेट में गोल्ड जीता। मंडल की पुरुष एवं महिला टीम ने टेनिस सिंगल, शतरंज, कैरम सिंगल एवं डबल , एथेलेटिक्स सिंगल एवं टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। मंडल की महिला खिलाड़िओं ने स्विमिंग, हेयरस्टाइल और ग्रुप फ्लावर मेकिंग में कांस्य पदक जीता।

डांस एवं वोकल कला में भी अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए वडोदरा मंडल ने कलचरल शील्ड भी जीत ली है। मीट में आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं में सोलो डांस, ग्रुप डांस , वोकल और इंस्ट्रुमेंटल प्रतियोगिताएं में वड़ोदरा मंडल के अधिकारियों और उनकी पत्नियों तथा रेलकारियों के बच्चों ने कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेजोड़ प्रदर्शन किया और प्रधान कार्यालय एवं सभी मंडलों के बीच श्रेष्ठ प्रदर्शन कर कल्चरल शील्ड को हासिल किया। ग्रुप डांस के अधिकारी और उनकी पत्नी तथा 10 वर्ष या उससे कम वर्ष के बच्चों के वर्ग में वड़ोदरा मंडल प्रथम रहा। सोलो डांस में अधिकारी और उनकी पत्नी वर्ग में हेतल शर्मा और 10 -14 वर्ग के बच्चों के वर्ग में तनीषा रंजन ने प्रथम, 10 वर्ष या उससे कम वर्ष की श्रेणीं में इवांशी कौशिक ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वोकल में 10 -14 वर्ग के बच्चों के वर्ग में आर्य अध्यापक द्वितीय और 10 वर्ष या उससे कम वर्ष की श्रेणीं में शानवी अध्यापक तृतीय स्थान पर रहीं। इंस्ट्रुमेंटल में 14 -18 वर्ग के बच्चों के वर्ग में शौर्य कुमार प्रथम और 10 -14 वर्ग के बच्चों के वर्ग में आर्य अध्यापक द्वितीय स्थान पर रहे। मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने सभी विजयी खिलाड़िओं को उनके खेल प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कल्चरल और स्पोर्ट्स को अभिव्यक्ति का एक साधन बताया और नयी पीढ़ी से इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेने की अपील की।

विसावदर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को मार्केट मिले उस दिशा में AAP विधायक गोपाल इटालिया का किसानहितैषी प्रयास

▸▸ मोटा कोटड़ा गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग मुद्दे पर किसानहितैषी बैठक में विधायक गोपाल इटालिया उपस्थित रहे

▸▸ विसावदर–भेंसाण के ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा करने की तैयारी: गोपाल इटालिया

▸▸ विसावदर भेंसाण के किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, लेकिन लोगों तक इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं: गोपाल इटालिया

▸▸ ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्लेटफॉर्म खड़ा करने तथा ई-कॉमर्स, मार्केटिंग, पैकेजिंग जैसे काम कर सकने वाले लोग मुझसे संपर्क करें: गोपाल इटालिया

(जीएनएस)। अहमदाबाद/जूनागढ़/गुजरात। आम आदमी पार्टी के विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया ने आज प्राकृतिक खेती के मुद्दे पर विसावदर तालुका के मोटा कोटड़ा गांव में एक किसानहितैषी बैठक में भाग लिया। विसावदर और भेंसाण जूनागढ़ तालुका में प्राकृतिक खेती (ऑर्गेनिक फार्मिंग) करने वाले किसानों को मार्केट मिले, किसानों को लाभ हो और प्राकृतिक खेती में क्या-क्या किया जा सकता है, इसकी जानकारी देने के उद्देश्य से इस किसानहितैषी बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के संदर्भ में विधायक गोपाल इटालिया ने फेसबुक लाइव के माध्यम से कहा कि प्राकृतिक खेती क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं और विधायक के रूप में मैं किसानों की किस प्रकार मदद कर सकता हूं, इस बारे में जानकारी प्राप्त करने में मेरी रुचि थी, इसी कारण हमने इस बैठक का आयोजन किया। गिरनार पर्वत के चारों ओर का 90 प्रतिशत क्षेत्र विसावदर-भेंसाण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। मतलब इस क्षेत्र के किसानों के पास उपजाऊ जमीन है, पानी है, जंगल हैं, पहाड़ हैं और मेहनती किसान हैं, लेकिन एक अच्छा मार्केट नहीं है। इसलिए आने वाले समय में और बैठकें करके ऑर्गेनिक खेती का मार्केट किस प्रकार खड़ा किया जाए, इसका प्लान बनाएंगे। गोपाल इटालिया ने कहा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म खड़ा करने में मदद कर सकते हैं, साथ ही सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग जैसे कार्यों के संदर्भ में जो भी लोग हमारी मदद करना चाहते हों, वे हमसे संपर्क करें। गुजरात भर से लोग इस कार्य को सपोर्ट देंगे और भेंसाण-विसावदर के किसानों से ऑर्गेनिक वस्तुएं खरीदेंगे तो मेरे किसानों का उत्साह बढ़ेगा। फिलहाल ऐसे एक सामान्य विचार के साथ यह बैठक की गई थी और आशा है कि आने वाले समय में हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे।

गुजरात सरकार

हर घर स्वदेशी
घर-घर स्वदेशी

सुशासन के संकल्प के साथ...जनकल्याण के सेवा-यज्ञ हेतु...समर्पित एवं निरंतर कार्यशील सरकार...

हम, माननीय प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी के

'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार कर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लेते हैं।

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य महोत्सव में

माननीय राज्यपाल

श्री आचार्य देवव्रत के

कर-कमलों द्वारा

ध्वजवंदन समारोह

दिनांक: 26 जनवरी 2026, सोमवार | समय: सुबह 9:00 बजे
स्थल: हेलीपैड ग्राउंड, नई कोर्ट के सामने, मलुपुर, ता. थराद, जि. वाव-थराद

प्रेरक उपस्थिति

श्री भूपेन्द्रभाई पटेल
माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात

श्री शंकरभाई चौधरी
माननीय अध्यक्ष, गुजरात विधानसभा

- वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट (कच्छ-सौराष्ट्र) राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ
- राज्य के 25,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को ₹450 करोड़ की सहायता
- थैलेसीमिया उन्मूलन में गुजरात बना रोल मॉडल, राज्य में 15.50 लाख से अधिक लोगों की थैलेसीमिया जाँच
- भक्ति, श्रद्धा और स्वाभिमान से ओतप्रोत वातावरण में “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व” का ऐतिहासिक आयोजन
- राज्यव्यापी जलापूर्ति ग्रिड से प्रतिदिन 320 करोड़ लीटर पानी का वितरण
- साणंद में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली सुविधा का शुभारंभ
- राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात ने पाँचवीं बार ‘बेस्ट परफॉर्मर स्टेट’ का गौरव प्राप्त किया
- ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना के शुभारंभ में गुजरात अग्रणी

आइए, हम सभी स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास पर गर्व करें तथा बंधुत्व एवं समानता की भावना को और अधिक सुदृढ़ बनाएँ।

> “आइए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोकतंत्र के मूल्यों को और सुदृढ़ करें। 'हर घर स्वदेशी' के मंत्र को अपनाकर विकसित गुजरात के माध्यम से विकसित भारत @2047' के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध बनें।”

- श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

वोकल फॉर लोकल

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण : CMOGujarat CMOGujarat CMOGujarat CMOGujarat